संख्या-44/2024/33/41-1-2024-001-CN-1729844-2023

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक 17 जनवरी,2024**

विषय:-उ0प्र0 ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7233/बजट विषयक/2023-2, दिनांक 27.12.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 50.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उ0प्र0 ईको टूरिज्म विकास बोर्ड के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो हेतु पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-535/2023/आई/360687/001-41-1099-87-2023-266-बजट-2023 दिनांक 02.08.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-44 के राजस्व मद के लेखा शीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-20-उ0प्र0 ईको टूरिज्म बोर्ड, लखनऊ-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रु0 200.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-44 के राजस्व मद के लेखा शीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-20-उ0प्र0 ईको टूरिज्म बोर्ड, लखनऊ-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रु0 200.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि आपके **निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व मदवार व्यय की कार्ययोजना तैयार करके शासन को प्रस्तुत की जायेगी एवं कार्ययोजना शासन से अनुमोदित होने के पश्चात ही धनराशि व्यय की जायेगी** तथा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत परियोजना/कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पर्यटन अनुभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश दिनांक 02.08.2023 में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करा लिया गया हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। अत: जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से मदवार व्यय विवरण शासन को उपलब्ध कराते हुए सक्षम स्तर से वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही व्यय सुनिश्चित किया जाय।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-3227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17 मार्च, 2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद/प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। विभिन्न मदों में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

(4) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय। विभाग के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार सम्भावित व्यय की फेजिंग की जाय तथा यथासंभव व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए समान रूप से ही की जाय।

(7) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उनका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) पूर्व में निवर्तन पर रखी गयी धनराशि एवं वर्तमान में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का सक्षम स्तर से अनुमोदित उपयोगिता प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) स्वीकृति धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जाय।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 044 लेखा शीर्षक 3452808002000 उ.प्र. इको टूरिज्म बोर्ड, लखनऊ मानक मद-20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-449-X-2023-24, दिनांक: 15-01-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5. उप निदेशक (प्रशासन) पर्यटन, उ0प्र0।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।